• ई-सेवा केंद्र

ई-सेवा केंद्र एक पायलट आधार पर प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालयों और एक जिला न्यायालय में बनाए गए हैं। यह वादियों (litigants) को मामले की स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त करने और निर्णयों व आदेशों की प्रतियां प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। ये केंद्र मामलों की ई-फाइलिंग (e-filing) में सहायता भी प्रदान करते हैं। ये ई-सेवा केंद्र आम आदमी और उसके न्याय तक पहुँचने के अधिकार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करते हैं। ई-सेवा केंद्र की सुविधा तीनों स्थानों- जिला न्यायालय परिसर उत्तरकाशी, सिविल न्यायालय परिसर पुरोला और सिविल न्यायालय परिसर बड़कोट में प्रदान की गई है।

• ई-सेवा केंद्र में दी जाने वाली सुविधाएं

- ई-सेवा केंद्र वादियों और वकीलों के लिए निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करेंगे:-
- मामले की स्थिति, सुनवाई की अगली तारीख और अन्य विवरणों के बारे में पूछताछ का निपटारा करना।
- प्रमाणित प्रतियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान करना।
- हार्ड कॉपी याचिकाओं की स्कैनिंग, ई-हस्ताक्षर जोड़ने, उन्हें सीआईएस पर अपलोड करने और फाइलिंग नंबर बनाने से लेकर याचिकाओं की ई-फाइलिंग की सुविधा प्रदान करना।
- ई-स्टांप पेपर/ई-भुगतान की ऑनलाइन खरीद में सहायता करना।
- आधार आधारित डिजिटल हस्ताक्षर के लिए आवेदन करने और प्राप्त करने में सहायता करना।
- एंड्रॉइड और आईओएस के लिए ई-कोर्ट्स के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने में सहायता करना और उसका प्रचार करना।
- जेल में बंद रिश्तेदारों से मिलने के लिए ई-मुलाकात अपॉइंटमेंट की बुकिंग में सुविधा प्रदान करना।
- छुट्टी पर गए जजों के बारे में प्रश्नों का निपटारा करना।
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति और सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति से निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्राप्त करने के तरीके के बारे में लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करना।
- वीडियो कॉन्फ्रेंस कोर्ट सुनवाई की व्यवस्था और आयोजन की विधि की व्याख्या करना।
- ईमेल, व्हाट्सएप या किसी अन्य उपलब्ध माध्यम से न्यायिक आदेशों/निर्णयों की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराना।